

सम्पादकीय

निर्यात पर जोर

वित्त वर्ष 2021–22 में भारत ने 420 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं तथा 254 अरब डॉलर मूल्य की सेवाओं का रिकॉर्ड निर्यात किया था। लगातार बढ़ते निर्यात से यह इंगित होता है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय बाजार में भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन निर्यात के साथ–साथ आयात में बढ़ती चिंता की बात है, जिसके कारण व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 के पहले चार महीनों (अप्रैल–जुलाई) में ही व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। इस पश्चातभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों से निर्यात बढ़ाने का आव्हान महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रारंभिक दौर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा वैशिक आपूर्ति शशंखला में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया था। बड़ी आवादी होने के कारण भारतीय बाजार का आकार भी बहुत बड़ा है। अगर हम स्थानीय उत्पादों का उपभोग करें, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार व आमदनी के अधिक अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, हम कई वस्तुओं के आयात को कम कर व्यापार घाटे को भी कम कर सकते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक पहलें की गयी हैं, जिनमें दो कार्यक्रम— उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ स्कीम) तथा कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किसान व निर्यातकों के बीच संपर्क अभियान— विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पीएलआइ स्कीम के तहत वैशिक स्तर के गुणवत्तापूर्ण निर्यात के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें उत्पादकों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग मुहैया कराया जा रहा है। कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार बढ़त है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारियों के सहयोग से किसानों से निर्यातकों का संपर्क कराने की प्रक्रिया चला रही है। एक बड़ी समस्या यह है कि राज्यों के अधिकारी तथा उत्पादकों को निर्यात प्रक्रिया के बारे कम जानकारी होती है। ऐसी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। निर्यात पर बल देने के प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह का महत्व इसलिए भी है कि अगर निर्यात के लायक अच्छी गुणवत्ता के वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को भी बेहतर चीजें उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया है कि अगर उत्पादन और निर्यात में वशद्वि होती है, तो अधिक राजस्व संग्रहण भी हो सकेगा। अगले वर्ष भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता मिलेगी। उन्होंने राज्यों को इस मौके का अधिकाधिक लाभ उठाने की सलाह भी दी। इस समूह के देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनके साथ गहरे व्यापारिक संबंध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ राज्यों के लिए भी लाभकारी होंगे। आशा है कि राज्य सरकारें प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर अमल कर निर्यात बढ़ाने को प्राथमिकता देंगी।

गलत नातया का चुनाता दा जाना चाहए



स अपने दिल का बात कह रहा है,
जिन्हाँने बार-बार सुप्रीम कोर्ट की
जिम्मेदारियों के परिभाषित क्षेत्रों से
अधिक होने की शिकायत की है। सुप्रीम
कोर्ट के कई फैसले इसके न्यायिक
दायरे से आगे निकल गए हैं। हमने
कहा है कि यह एक नीतिगत निर्णय
है, फिर भी अदालत आगे बढ़ी। अक्सर
अदालत नीतिगत फैसले देती रही है

जो विवाचक का ऐसा जोर ऐसा करना
को पारित करने के लिए कह रही है।
शक्तियों का पृथक्करण है और इसे द
यान में रखा जाना चाहिए, वेणुगोपाल
ने एक पीठ को बताया, जिसके सदस्यों
में से एक स्वयं डीवाई चंद्रचूड़ थे।
गौरतलब है कि जब कोर्ट ने ताजा
जीएसटी मामले में इस मुद्दे को उठाया
था, तब यह नरम सुझाव के तौर पर

जिन्होंने बार-बार सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों के परिभाषित क्षेत्रों से अधिक होने की शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इसके न्यायिक दायरे से आगे निकल गए हैं। हमने कहा है कि यह एक नीतिगत निर्णय है, फिर भी अदालत आगे बढ़ी। अक्सर अदालत नीतिगत फैसले देती रही है को पारित करने के लिए कह रही है। शक्तियों का पृथक्करण है और इसे द्यान में रखा जाना चाहिए, वेणुगोपाल ने एक पीठ को बताया, जिसके सदस्यों में से एक स्वयं डीवाई चंद्रचूड़ थे। गौरतलब है कि जब कोर्ट ने ताजा जीएसटी मामले में इस मुद्दे को उठाया था, तब यह नरम सुझाव के तौर पर

आवरम्भणाथ ह श्यामलाल का धागदान



13 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। काव्य के प्रति इनका लगाव बचपन से था। पंद्रह वर्ष की उम्र में ही इहोंने हारिगीतिका, सवैया और भास्तुरी कांग्रेस का सिल

वीरों को हरणाने वाला, मातृभूमि का रहने लगी। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन तन—मन सारा की रचना की। इस के समय लगभग एक लाख कांग्रेस गीत को कान्ग्रेस ने स्वीकारा और 1925 प्रतिनिधियों व नेताओं के साथ यह में कानापार कांग्रेस अधिवेशन में गाया।

न कानूनुर प्रव्रत्त जावपराना न पह
गीत धजारोहण के दौरान पहली बार
सामूहिक रूप से गाया गया।

तब से आजादी मिलने तक यह गीत
कांग्रेस के सभा, सम्मेलन, अधिवेशन
और आंदोलन के समय गाया जाता
रहा। आजादी की लड़ाई के दौरान यह
गीत सभी का प्रिय बन गया। इस
गीत ने देश के जनमानस में चेतना
जागृत करने का कार्य किया। इसी

द्यालय को स्थापना की, जो अब सर वैश्य इंटर कॉलेज के नाम से जाता है। इस कॉलेज की पत्रिका भी गुप्त जी ने कई वर्षों तक प्राप्तादन किया। इन्होंने एक अनाथालय और बालिका विद्यालय की भी स्थापना की। वैश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों का खत्म करने और विधवाओं के नविवाह के लिए वह जीवनभर वर्घररत रहे। वह इतने स्वाभिमानी थे कि जीवन में अभाव के बावजूद किसी सामने उसका जिक्र तक नहीं करते। एक दिन नरबल में गणेश सेवा श्रम जाते हुए इनके पैरों में कांच स गया, जिससे इनका पांव पकड़ा। कानपुर के उर्सला अस्पताल में उपचार का ऑपरेशन हुआ, पर इनका आश्चर्य दिनों-दिन गिरता गया। वह बर मरणसन्न अवस्था में थे, तब उनपुर से प्रकाशित दैनिक शाजर समेत पश्चिम का समर्थन रहा। सत्र के दशक के शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के प्रयासों से चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जोड़ा गया और अमेरिकन व चीन के बीच संबंधों का नया दौर प्रारंभ हुआ। तब अमेरिका ने शन चाइना पॉलिसीश को अपनाया, लेकिन 1979 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसे अमेरिका-ताइवान संबंध समझौता कहा जाता है। इसके तहत यह प्रावधान है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका हर तरह से सहयोग मुहैया करायेगा, पर यह स्पष्ट नहीं था कि आवश्यकता पड़ने पर ताइवान के लिए अमेरिका चीन से लड़ने आयेगा। तब ऐसी स्थिति की आशा भी नहीं थी, क्योंकि चीन कमज़ोर था, लेकिन चीन पिछले कुछ समय से अमेरिका की वैश्विक प्रधानता को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। इसे अमेरिका ने गंभीरता से लिया है और उसका पूरा ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित हो रहा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके तथा उसके साथ प्रतिस्पर्द्धा की जा सके। इन परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका किसी तरह के संघर्ष के पक्ष में नहीं है। चीन भी ऐसा नहीं चाहता है। ताइवान का मुद्दा चीन के लिए श्रेष्ठ लाइनश है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी ताइवान में अमेरिका से कोई उच्चस्तरीय यात्रा होती है, तो चीन की प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण होती है। जब से रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका की यह कोशिश रही है कि चीन रूस को हथियारों की आपूर्ति न कर सके। चीन भी कहता रहा है कि वह रूस को सैन्य सहयोग नहीं दे रहा है। इस तरह अमेरिकन और चीन के बीच इस मामले पर एक तरह की सहमति चली आ रही है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैसी पेलोसी की यात्रा ने वर्तमान समीकरण में हलचल पैदा कर दी है। वे हमेशा से चीन नीतियों का विरोध करती रही हैं। उन्होंने थियानमन स्कवेयर आंदोलन को भी समर्थन दिया था। वे पहले भी ताइवान की यात्रा कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कभी भी ताइवान की स्वतंत्रता की मांग नहीं की है, लेकिन इस समय चीन बेहद नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको चारों ओर से धोरे की कोशिश हो रही है। चीन अभी दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वह अमेरिका से बराबरी के साथ बातचीत करना चाहता है। अमेरिका भी अभी यह नहीं चाहता था कि स्थिति बिगड़े, क्योंकि जलदी ही जी-20 समेत कुछ अहम बैठकें होनी हैं। जब पेलोसी ने अपने एशिया दौरे की घोषणा की थी और उसमें ताइवान जाने

नगर संस्करण में इनकी आर्थिक हायता किये जाने का अनुरोध किया था। इससे पहले की सहायता ललती 10 अगस्त, 1977 की रात वह नर्सें सदा-सदा के लिए छोड़ दुनिया विदा हो गये। वर्ष 1973 में इन्हें दमशी से सम्मानित किया गया था। अब यिंडना है कि राष्ट्र के इस महान पूत के अवसान के बाद न तो एक दिन झंडा झुकाया गया, न उनके तिम संस्कार में राज्य सरकार के जी मंत्री ने भाग ही लिया। जिस किं के लिखे गीत भीड़ को नुशासित सैनिकों में बदलने की क्षमता बते थे, भारत मां के इस अमर सपूत ने नेतृत्व भले ही भुला दे, लेकिन य कभी नहीं भूलेगा। आजादी की डाई के इतिहास में उनका नाम सदा की बात थी, तो मेरा मानना है कि उसमें बाइडेन प्रशासन से विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

बाइडेन प्रशासन की ओर से जो बयान आये, उनमें कहा गया कि पेलोसी हाउस स्पीकर हैं और वे कहीं भी जा सकती हैं, उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिकी सत्ता में हाउस स्पीकर का पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे स्थान पर आता है। चीन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसे यह यात्रा स्वीकार्य नहीं है। इसमें पेलोसी के चीन विरोध का इतिहास भी एक कारक था। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लंबी टेलीफोन वार्ता हुई थी, तो उसमें भी इस दौरे पर बातचीत हुई थी और राष्ट्रपति शी ने तो यहां तक कह दिया था कि आग से खेलना ठीक नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि जब चार दशों का पेलोसी का कार्यक्रम प्रकाशित हुआ, उसमें ताइवान का नाम नहीं था, लेकिन जब कोई महाशक्ति ऐसी घोषणा कर देता है, तो उसका पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल यह है कि क्या पेलोसी की यात्रा से विश्व शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए कोई लाभ हुआ, तो इसका उत्तर नकारात्मक है। यह तो एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी जैसी बात है। एक तो ताइवान पर चीन का पुराना दावा है और उस पर वह सेन्य कार्रवाई कर कब्जा भी कर सकारात्मक है, यह उसके संविधान में लिखा हुआ है, पर वह बातचीत और आक्रामक बयान देकर फिलहाल काम चलाना चाहता है। मुझे लगता है कि पेलोसी का दौरा अमेरिका की घरेलू राजनीति की विश्वासाओं और वैश्विक राजनीतिक स्थिति को ठीक से नहीं समझने का परिणाम है। चीन ने सेन्य अभ्यास की घोषणा भी यह सोच कर की थी कि शायद अमेरिका इस दौरे पर पुनर्विचार करेगा। बहरहाल, यह अभ्यास ताइवान को एक सबक सिखाने के इरादे से भी प्रेरित है। जापान के एक निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के कारण चीन ने उसके विदेश मंत्री के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। इसके साथ ही ताइवान पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाये गये हैं। अगर रविवार तक सेन्य अभ्यास समाप्त हो जाता, तो यह माना जाता कि मामला नियंत्रण

खारथ्य सेवाओं के सुधार के लिए कोविड के सबक



हुंचाया। फिर भी आमतौर पर जो अनुभव कोविड काल का रहा, उसमें देखा गया कि न केवल गरीब लोगों के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न ही थीं, बल्कि जो पैसे खर्च करने में सक्षम थे, उहाँे भी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से वो सेवाएं नहीं मिल सकीं जिनके लिए वो बरसों-बरस भारी रकम लुटाते रहे हैं। ज्यादातर वहीं सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर और स्टाफ काम आया जिसे निजीकरण के युग में हाशिये पर धकेला जा रहा था, जिनकी जमीनें बेची जा रही थीं, जिनके स्टाफ को ठेके पर रखा जा रहा था और जहां से दवाइयां मुफ्क्त देना बंद किया जा रहा था। 1990 के दशक के बाद से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के संजाल को धीरे-धीरे नाकारा करना शुरू कर दिया गया था। अस्पतालों से दवाएं गायब हो गई थीं, जांचों के लिए मरीजों जाने का लगा रहा। लेकिन लाखों लाखों लोगों ने जाने लगा था। एक्स-रे, ईंसीजी मरीजों या अन्य जरूरी उपकरण भी सरकारी अस्पतालों में थीक-ठाक हालत में नहीं मिलते थे। सरकारी अस्पतालों के बजट में सरकार ने कटौती कर दी थी। कुल मिलाकर, धीरे-धीरे सरकारी अस्पतालों से मरीजों का विश्वास कमज़ोर कर दिया गया था और करीब-करीब 80 फीसदी मरीज मजबूरी में निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ मुड़ गए थे। कोविड की दूसरी लहर में सरकार ने निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बाध्य किया। बाध्यता के चलते निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन सब जानते हैं कि कोविड के मरीज का निजी अस्पतालों में इलाज का पैकेज लाखों रुपये रोज का था। पंजाब, दिल्ली और केरल ही ऐसे राज्य थे जहां सरकार ने बेतहाशा महंगे कर

र गए इलाज के मामले में कुछ तक्षेप किया और मरीजों को राहत लवाई। दवाओं की जमाखोरी नेत्रेआम हुई। राजनेताओं ने जरूरत होने पर भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं उपकृत करने के लिए जिस दवा नाम चला, वो थोक में खरीदकर ली। श्रेमडेस्वीरेश के नाम पर दे पानी के इंजेक्शन भी जरूरतमंदों एक-एक लाख रुपये में बेच दिए। इन सभी कारणों से सरकारी अस्पतालों पर काफी अतिरिक्त भार गया, जबकि उन्हें 1991 के बाद धीरे-धीरे कमज़ोर करने की प्रक्रिया ले ही जारी थी। जिन मरीजों को ट में कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन ई और बीमारी का लक्षण उन्हें नहीं उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में कर दिया गया। नतीजा ये हुआ जो छोटी-मोटी बीमारी के भी ज थे, जिनका सामान्य स्थितियों घर पर ही इलाज हो जाता था, केन कोरोना के डर ने उन्हें अपनाएँ रखी थीं और उन्हें पारा-पारा

आज का राशिफल

अंदर हीन भावना न आने दें। बाहर की दुनिया में समय देने से अच्छा है कि थोड़ा घर में समय देने की चेष्टा करें। कुछ नयी आकंक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी।

बुष्म :— बुद्धिमत्ता द्वारा प्रत्येक दिशा और स्वच्छ योजनाओं की ओर केंद्रित हों। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है किंतु भावनात्मक अपेक्षाएं कष्ट की जननी बनेंगी।

वशिचक :— निकट संबंधों में मधर

न स्वयं का पारगत साधन करना। भौतिकता की लोलुपतावश दूसरों के चढ़ाने में आकर अपनी आर्थिक क्षति कर सकते हैं। जीवन साथी से कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद संभव। वाणी का प्रयोग करा क्षमता से आधारित जिम्मेदारियां आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। कार्यक्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।

मकर :- भावनाओं पर नियंत्रण खेलने का एक विकास होगा। रोजगार में अच्छे लाभ के आसार बनेंगे। घर में खुशहाल वातावरण रहेगा।

के आसार हैं। रोजगार में अच्छी आशाएं प्रसन्नता लाएंगी किंतु परिवारिक चिंताओं से मन ग्रसित होगा। अंतरिक प्रतिभाओं द्वारा सगे—संबंधों में प्रभावी बनेंगे। योजनाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को समयानुकूल पूर्ण करने में सक्षम होंगे। धनागम के ने स्रेत बनेंगे। परिवार में खुशहाल स्थिति रहेगी।

सिंह :- घरेलू दायित्वों की पूर्ति हेतु सक्रियता से आपकी महत्ता बढ़ेगी। अंतमरुखी स्वभाव को त्याग बाह्यमुखी बने। पूजा-पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। आलस्य त्यागें।

कन्या :- भौतिकता के आधार पर थोड़ा असंतोष हो सकता है। सगे-संबंधों में व्यवहार कुशल बने। कुछ नयी अभिलाषाएं आपको

जुन :- जरा नहरेकून दायित्व का कुशल पूर्ति हेतु समुचित साधन व्यवस्था के लिए मन चिंतित होगा। नौकरी-पेशे में अधिकारियों व सहकर्मियों के सहयोग से वातावरण सुखद होगा।

मीन :- अपनी भावुकता पर नियंत्रणरखें। हर रिश्ते में अपने अनुकूल अपेक्षा रखना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। माता के स्वास्थ के प्रति कुछ चिन्हाएं होंगी। जीवन साथी

हरात्साहरा करना पारपारक
वातावरण उत्साहित रहेगा।

क स्वास्थ क प्रात सतकता अपाकृत
है।

ਤਕਾਰ ਕੇ ਸਾਧਿਤੇ

ਤਾਇਵਾਨ ਪਦਤਖਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਧਿਗ

तत पश्चिम का समर्थन रहा। सतर के दशक के शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निकसन के प्रयासों से चीन को गराराष्ट्रीय समुदाय के साथ जोड़ा गया और अमेरिकन व चीन के बीच संबंधों का नया दौर प्रारंभ हुआ। तब अमेरिका श्वन चाइना पॉलिसीश को अपनाया, लेकिन 1979 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसे अमेरिका-ताइवान संबंध समझौता कहा जाता है। इसके तहत यह प्रावधान है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका तरह से सहयोग मुहेह्या करायेगा, पर यह स्पष्ट नहीं था कि आवश्यकता पड़ने पर ताइवान के लिए अमेरिका चीन लड़ने आयेगा। तब ऐसी स्थिति की आशा भी नहीं थी, क्योंकि चीन कमजोर था, लेकिन चीन पिछले कुछ समय से अमेरिका की वैश्विक प्रधानता को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। इसे अमेरिका ने गंभीरता से लिया है और उसका ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित हो रहा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके तथा उसके साथ प्रतिस्पर्द्ध की जा सके। इन परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका किसी तरह के संघर्ष के पक्ष में नहीं है। चीन भी ऐसा नहीं चाहता ताइवान का मुद्दा चीन के लिए श्रेष्ठ लाइनश है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता है। इसीलिए चीन भी ताइवान में अमेरिका से कोई उच्चस्तरीय यात्रा होती है, तो चीन की प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण होती है। जब से न-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका की यह कोशिश रही है कि चीन रूस को हथियारों की आपूर्ति न कर सके। चीन कहता रहा है कि वह रूस को सैन्य सहयोग नहीं दे रहा है। इस तरह अमेरिकन और चीन के बीच इस मामले पर तरह की सहमति चली आ रही है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैसी पेलोसी की यात्रा ने वर्तमान राजीकरण में हलचल पैदा कर दी है। वे हमेशा से चीन नीतियों का विरोध करती रही हैं। उन्होंने थियानमन स्कवेयर दोलन को भी समर्थन दिया था। वे पहले भी ताइवान की यात्रा कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कभी भी ताइवान की स्वतंत्रता की मांग नहीं की है, लेकिन इस समय चीन बेहद नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको नीतियों ओर से धोरने की कोशिश हो रही है। चीन अभी दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वह अमेरिका से बाबरी के साथ बातचीत करना चाहता है। अमेरिका भी अभी यह नहीं चाहता था कि स्थिति बिगड़े, क्योंकि जल्दी ही 20-समेत कछ अहम बैठकें होनी हैं। जब पेलोसी ने अपने एशिया दौरे की घोषणा की थी और उसमें ताइवान जाने

बात थी, तो मेरा मानना है कि उसमें बाइडेन प्रशासन से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। इडेन प्रशासन की ओर से जो बयान आये, उनमें कहा गया कि पेलोसी हाउस स्पीकर हैं और वे कहीं भी जा सकती उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिकी सत्ता में हाउस स्पीकर का पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सरे स्थान पर आता है। चीन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसे यह यात्रा स्वीकार्य नहीं है। इसमें पेलोसी के निरोध का इतिहास भी एक कारक था। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी ने निर्णय की लंबी टेलीफोन वार्ता हुई थी, तो उसमें भी इस दौरे पर बातचीत हुई थी और राष्ट्रपति शी ने तो यहां तक दिया था कि आग से खेलना ठीक नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि जब चार देशों का पेलोसी का कार्यक्रम प्रकाशित हुआ, उसमें ताइवान का नाम नहीं था, लेकिन जब कोई महाशक्ति ऐसी घोषणा कर देता है, तो उसका पीछे हटना बहुत दैरेकल होता है। अब सवाल यह है कि क्या पेलोसी की यात्रा से विश्व शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए कोई लाभ होगा, तो इसका उत्तर नकारात्मक है। यह तो एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी जैसी बात है। एक तो ताइवान पर चीन ने पुराना दावा है और उस पर वह सेन्य कार्रवाई कर कब्जा भी कर सकारात्मक है, यह उसके संविधान में लिखा हुआ है। पर वह बातचीत और आक्रमक बयान देकर फिलहाल काम चलाना चाहता है। मुझे लगता है कि पेलोसी का दौरा अमेरिका की घरेलू राजनीति की विशेषताओं और वैश्विक राजनीतिक स्थिति को ठीक से नहीं समझने का परिणाम है। उन ने सेन्य अभ्यास की घोषणा भी यह सोच कर की थी कि शायद अमेरिका इस दौरे पर पुनर्विचार करेगा। बहरहाल, अभ्यास ताइवान को एक सबक सिखाने के इरादे से भी प्रेरित है। जापान के एक निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के कारण चीन ने उसके विदेश मंत्री के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। इसके साथ ही ताइवान पर कुछ आर्थिक निर्बंध भी लगाये गये हैं। अगर रविवार तक सेन्य अभ्यास समाप्त हो जाता, तो यह माना जाता कि मामला नियंत्रण

